आजकल

कैसी हो सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा

■ डॉ. विजय अग्रवाल

सिविल सेवा परीक्षा में सीसेट के पेपर को क्वालीफाइंग पेपर किए जाने संबंधी सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। उल्लेखनीय है कि सीसेट के पेपर का अंग्रेजी माध्यम तथा इंजीनीयरिंग के छात्रों के पक्ष में होने के विरोध में परीक्षार्थियों ने काफी लंबा आंदोलन किया था। इस फैसले से खासतौर पर हिंदी पट्टी और ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षार्थियों के चेहरे खिल गई है...

सिविल सेवा परीक्षा में सीसेट के पेपर को क्वालीफाइंग पेपर किए जाने संबंधी सरकार का निर्णय न केवल स्वागत योग्य है, बल्कि अभिनंदनीय भी है। यह निर्णय देश के लोगों को यह विश्वास दिलाने वाला है कि 'हम समान अवसर वाले मौलिक अधिकारों से संपन्न एक सच्चे लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक हैं।' उल्लेखनीय है कि सीसेट के पेपर का अंग्रेजी माध्यम तथा इंजीनीयरिंग के छात्रों के बेहद पक्ष में होने के विरोध में परीक्षार्थियों ने काफी लंबा आंदोलन किया था। तब सरकार ने इस पेपर से अंगेजी भाषा संबंधी लगभग दस प्रतिशत अंकों वाले प्रश्नों को तत्काल हटा दिया था। अब सरकार ने इसे क्वालीफाइंग पेपर बनाकर परीक्षार्थियों के चयन पर पड़ने वाले इसके सीधे प्रभाव को निरस्त कर दिया है। अब परीक्षार्थियों को इसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाने होंगे। वैसे इसके पहले भी इसमें 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था। दो प्रतिशत अंकों के इस लाभ को बोनस कहा जा सकता है।

फिलहाल यह अंतिम निर्णय नहीं है। सरकार ने इस मुद्दे के साथ-साथ सिविल सेवा परीक्षा की पद्धति, योग्यता तथा अवसरों आदि प्रश्नों पर भी विचार करने के लिए एक समिति बनाई है। नई सरकार ने अब तक जनभावनाओं तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि कमेटी की रिपोर्ट में भी उसकी पर्याप्त झलक मिलेगी।

जहां तक प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों का सवाल है, इसके नए स्वरूप के बारे में कुछ विचारणीय तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह तो निर्विवाद है कि परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए छंटनी के एक चरण का होना जरूरी है। साथ ही इस बात पर भी शायद ही कोई दो राय हो कि इस चरण का स्वरूप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाला ही हो, क्योंकि तभी उत्तर-पत्रकों की जांच मशीन द्वारा संभव हो सकेगी। इस साल अगस्त में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में पहले की तरह ही सौ प्रश्नों वाला दो सौ अंकों का एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। इसी एक पेपर पर यह पूरा दारोमदार होगा कि वह मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 12-13 हजार विद्यार्थियों का चयन करे, क्योंकि सीसेट के पेपर को क्वालीफाइंग कर दिया गया है, जो इतने ही अंकों का होता था। यानी कि कुल दो सौ अंकों के दायरे में लगभग 12 हजार विद्यार्थियों का चुना जाना गणीतीय दृष्टि से इस काम में कोई बाधा नहीं है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया देश के सिविल सेवा के सर्वोच्च पदों के लिए की जाने-वाली भर्ती से जुड़ी हुई है। इसलिए पहले हम इसे पिछले वर्ष की परीक्षा के अंतिम परिणामों के आधार पर देखने और समझने की कोशिश करते हैं, जो न केवल तार्किक एवं व्यावहारिक ही होगा, बल्कि काफी कुछ रोचक भी।

पिछले वर्ष की चयनित सूची में टॉपर और अंतिम सफल परीक्षार्थी (जनरल कैटेगरी) के बीच 207 अंकों का अंतर था। यह संख्या कुल 2025 नंबरों के दायरे में थी और चयनित परीक्षार्थियों की कुल संख्या करीब एक हजार थी। महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य यह था कि 397वें और हजारवें परीक्षार्थी (लगभग 600) के बीच मात्र 21 अंकों का फर्क था। यानी समान अंक पाने वाले परीक्षार्थियों की संख्या औसतन तीस थी और वह भी तब जबकि कुल निर्धारित अंक थे 2025। ऐसे में 200 अंकों के फैलाव में 12 हजार परीक्षार्थियों की धक्का-मुक्की को महसूस किया जा सकता है। यह जरूरी और अत्यंत व्यावहारिक भी लगता है कि अंकों में फैलाव लाया जाए, ताकि न केवल चयन अपेक्षाकृत सुविधाजनक हो सके, बल्कि इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ताकि विभिन्न योग्यता, क्षमता और रुचि के विद्यार्थी सिविल सेवा में आकर इस अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बना सकें। इसके लिए सबसे अधिक औचित्यपूर्ण उपाय यह लगता है कि जनरल स्टडीज का ही एक अन्य पेपर रख दिया जाए।

सिविल सेवा परीक्षा में अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद है। यह समस्या सीधे-सीधे गैरअंग्रेजीभाषी विद्यार्थियों के खिलाफ जाती है

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2011 से पहले दूसरे पेपर के रूप में विद्यार्थी किसी भी एक विषय का चयन करते थे। इन विषयों की संख्या बीस के करीब थी। इन सभी विषयों में समानता लाने के लिए इनकी स्केलिंग की जाती थी, जिनका फार्मूला अभी तक सार्वजानिक नहीं किया गया है। सच तो यह था कि विषय के इस पेपर ने समानता के सिद्धांत के प्रति काफी संदेह पैदा कर दिया था। यह अच्छा ही हुआ कि द्वितीय पेपर के रूप में वैकल्पिक विषय को समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसके स्थान पर सीसेट लाकर समस्या को बढ़ा दिया गया था। इसलिए द्वितीय पेपर के रूप में वैकल्पिक विषय को फिर से लाना उचित नहीं होगा, बल्कि ज्यादा अच्छा तो यही होगा कि मुख्य परीक्षा से भी एक वैकल्पिक विषय की व्यवस्था को समाप्त करके सभी के लिए समान प्रश्नपत्र की प्रणाली लागू कर दी जाए। ऐसा करना अधिक न्यायपूर्ण होगा।

निश्चित रूप से इस दूसरे पेपर के विषय प्रथम प्रश्नपत्र से थोड़े अलग होंगे, लेकिन इस तरह मानो कि ये प्रथम प्रश्नपत्र को ही विस्तार दे रहे हों। उदाहरण के तौर पर अभी जो प्रथम प्रश्नपत्र आ रहा है, उसमें समाजशास्त्र, कला-साहित्य और संस्कृति, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, कंप्यूटर-विज्ञान, वर्तमान विचार-प्रणालियां, तत्वशास्त्र तथा प्रबंधन जैसे विषयों पर या तो प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं और यदि इनमें से किसी-किसी पर पूछ भी लिए जाते हैं, तो उनकी संख्या इतनी कम होती है कि विद्यार्थी उनके बारे में पढ़ने की बजाय उन्हें छोड़ देने की रणनीति बनाना उचित समझता है।

इसके साथ ही इस प्रश्नपत्र में सीसेट के भी कुछ प्रश्नों को रखा जा सकता है, जिनका अनुपात कुल प्रश्नों का लगभग दस प्रतिशत तक हो सकता है। यहां यह बताना उचित होगा कि वर्ष 2011 से पहले प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य-अध्ययन के पेपर में कुछ प्रश्न गणित, ग्राफ्स एवं तार्किक क्षमता वाले होते थे, किंतु काफी कम। जहां तक निर्णयन (डिसिजन मेकिंग) वाले प्रश्नों का सवाल है, इन्हें शामिल किया जा सकता है। यदि अनुवाद के साथ न्याय किया जा सके, तो बोधगम्यता वाले प्रश्न रखे जा सकते हैं, लेकिन उनका प्रतिषत पांच के आसपास ही होना पर्याप्त होगा। हालांकि भाषा ज्ञान की जांच मुख्य परीक्षा में की जाती है, लेकिन बोधगम्यता भाषा ज्ञान से काफी कुछ अलग है। यह भाषा की समझ से कई गुना अधिक अभिव्यक्त भावों एवं विचारों की सूक्ष्मता को पकड़ पाने की क्षमता से जुड़ी हुई है।

सिविल सेवा परीक्षा में अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद है। यह समस्या बहुत भयावह है, जो सीधे-सीधे गैरअंग्रेजीभाषी विद्यार्थियों के खिलाफ जाती है। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसका हल बहुत छोटा और सरल है। भारत में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाले दक्ष लोगों की कमी नहीं है, बशर्ते कि कंप्यूटर की तुलना में इंसानों पर अधिक भरोसा किया जा सके। आशा की जा रही है कि अगस्त में होने वाली परीक्षा छात्रों को आश्वस्त कर देगी कि इस समस्या का भी समाधान कर दिया गया है।

हालिया बदलावों से एक उम्मीद पैदा होती है कि सरकार सिविल सेवा में पूरे देश के छात्रों को समान अवसर देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सीसेट के शिकार रहे लाखों अभ्यर्थियों से यह उम्मीद की जाती है कि अब उनका प्रदर्शन इस परीक्षा में बेहतर होगा और कोई खास भाषा अथवा कोई खास प्रणाली उनके चयन को बाधित नहीं कर सकेगी।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)

समान अवसर की पहल

■ प्रभांशु ओझा

आखिरकार सिविल सेवा में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के अभ्यर्थियों की मेहनत रंग लाई और उनके चयन में सबसे बड़ी बाधा बने सीसेट को सरकार की तरफ से विज्ञप्ति जारी करके क्वालीफाइंग कर दिया गया जो बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। अब संघ लोक सेवा आयोग ने भी अपने नोटिफिकेशन में सरकार की इस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है। सरकार की महत्वपूर्ण अनुशंसाओं में शामिल है कि भारत सरकार एक समिति गठित करेगी जो सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े विभिन्न पक्षों पर विचार करेगी। विभिन्न पक्षों में अर्हता, पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना और संरचना आदि शामिल हैं। सीसेट के पेपर में अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा पिछले वर्ष की तरह इस बार भी महत्वहीन रहेगा। इसका अर्थ है कि या तो अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न आएंगे ही नहीं और अगर आए तो उनके अंक नहीं जुड़ेंगे। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पेपर-2 (सीसेट) क्वालीफाइंग रहेगा और इसे क्वालीफाई करने के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाने जरूरी होंगे और इस पेपर के प्राप्तांक को प्रारंभिक परीक्षा की योग्यता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। सीसेट लागू होने के वर्ष यानी 2011 के ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास इस परीक्षा के सभी मौके खत्म हो गए हैं उन्हें भी एक अतिरिक्त मौका दिया गया है। कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि यह निर्णय केवल हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह सही है कि इस निर्णय से हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के एक बड़े तबके ने राहत की सांस ली है, परंतु यह निर्णय उतना ही अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी था जितना की हिंदी भाषी अभर्थियों के लिए। दूसरी बात यह कि यह निर्णय अंग्रेजी भाषी अभ्यर्थियों के लिए किसी भी रूप में नकारात्मक नहीं है, बल्कि मानविकी और कला क्षेत्र के तमाम अभ्यर्थी चाहे वे हिंदी माध्यम के हों या अंग्रेजी माध्यम के, दोनों के लिए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का दूसरा पेपर जिसे सीसेट कहा जाता है, में बेहतर अंक लाकर प्रारंभिक परीक्षा को क्वालीफाई करना असंभव सा हो गया था। वही इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस के तमाम अभ्यर्थी लाभ लाभ की स्थिति में रहते थे। सीसेट में सामान्य तौर गणित, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन अनिवार्य से संबंधित सवाल पूछे जाते थे और ऐसे प्रश्नो में मानविकी पृष्ठभूमि तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के अभ्यर्थी प्रतियोगिता से बाहर हो जाते थे, भले ही उन्होने सामान्य अध्ययन के पेपर में बेहतर प्रदर्शन किया हो। वही कुछ खास पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्नपत्र में कम अंक लाकर भी द्वितीय प्रश्नपत्र के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में तो चयनित हो जाते थे, परंतु मुख्य परीक्षा में उनके अंक बेहतर नहीं रहते थे। हालात यहां तक पहुंचे कि सीसेट से पहले जितने अंकों पर अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता था उससे बहुत काम अंक लाकर तमाम अभ्यर्थियों ने टॉपर्स में अपनी जगह बनाई।

खुद लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जहां संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, ने अपनी तमाम रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि की कि सीसेट लागू होने के बाद आने वाले उम्मीदवार का प्रदर्शन एकेडमी में संतोषजनक नहीं है और वे एक कुशल प्रशासक के विभिन्न मानकों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं।

वर्तमान सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है कि उसने इस चीज को समझा और एक ऐसा निर्णय लिया जिससे इस परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके और कुशल प्रशासकों का चयन किया जा सके। इस निर्णय ने ग्रामीण और पिछड़ी पृष्ठभूमि के उन तमाम अभ्यर्थियों के सपनों को नए पंख दिए हैं जो सीसेट आने के बाद हताश और निराश होकर इस परीक्षा की तैयारी छोड़ चुके थे। तर्क यह दिया जाता था कि सीसेट में पूछे जाने वाले तमाम सवाल दसवीं के स्तर के है, परंतु असलियत यह है कि इस प्रश्नपत्र के तमाम सवाल यह परीक्षण करते थे कि कम समय में कौन सा अभ्यर्थी कितने सवालों को हल कर लेता है जिसमें निश्चित रूप से वे अभ्यर्थियों फायदे में रहते थे जो मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पृष्ठभूमि से आते थे। अगर सीसेट लागू होने के बाद हम आंकड़ें उठा कर देखें तो कुल चयन में इस पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और टॉपर्स में वही अभ्यर्थी रहे हैं जो आइआइटी, एम्स और आइआइएम जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से पढ़े हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)